फरीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो के लिये बजट में न कोई पैसा रखा गया है और न ही रखा जायेगा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एनआईटी क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में इस बात पर अफसोस जताया कि फरीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो के लिये एक रुपया भी नहीं रखा जबकि खट्टर वर्षों से लगातार इसके निर्माण की घोषणायें करते आ रहे हैं। लगता है कि विधायक नीरज शर्मा साप्ताहिक 'मज़दूर मोर्चा' नहीं पढ़ पाते। भोली-भाली जनता की भांति वे भी घोषणावीर खट्टर की घोषणायें सुन-सुन कर खुश होते रहते हैं। इसके विपरीत 'मज़दूर मोर्चा' बीते छह-सात वर्षों से लगातार यह लिखता आ रहा है कि ऐसी कोई मैट्रो लाइन बनने वाली नहीं है। बनाने की जरूरत ही क्या है जब लोग घोषणावीरों की झूठी घोषणाओं से ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

मोर्चा ने यह भी स्पष्ट लिख दिया है कि गुड़गांव जाने के जिस रूट का ढिंढोरा सरकारी भोंपूओं द्वारा पीटा जा रहा है, उसकी अपेक्षा दिल्ली-मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) तुगलकाबाद-महरौली-एयरपोर्ट व रूट पर काम कर रही है। इसके लिये काम तेज़ी से चल रहा है। जाहिर है कि यह काम पूरा होने के बाद बल्लबगढ़ से बारास्ता तुगलकाबाद-महरौली होते हुए गुड़गांव पहुंचा जा सकेगा।

फ़रीदाबाद से सीधे गुड़गांव मैट्रो का बाजा केवल इसलिये बजाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन-जायदादों के भाव उछाल मार सकें और धंधेबाज इससे मोटा-मुनाफ़ा कमा सकें। इसके अलावा इस घोषणा से लोगों को बहका कर चुनाव में वोट बटोरे जा सके। समझने वाली बात यह है कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में डूबी जो सरकार अपने मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, स्कूलों आदि को चलाने के लिये पैसा उपलब्ध न करा सकती, वह भला मैट्रो के लिये हजारों करोड़ कहां से लायेगी? इतना ही नहीं वेतन खर्च बचाने के लिये चार लाख सरकारी कर्मचारियों की जगह मात्र दो लाख से ही काम चलाने वाली सरकार के बहकावे में आम आदमी आ जाये तो कोई खास बात नहीं, लेकिन नीरज शर्मा जैसे राजनेता से तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती।

डीएमआरसी कर चुका है खारिज

मालूम हो कि 2016 में बदरपुर-फरीदाबाद मेट्रो ट्रैक शुरू होने के साथ ही भाजपा नेताओं ने जनता को बहकाने के लिए फरीदाबाद-गुड़गांव मेट्रो लाइन बिछाने की घोषणा की थी। डीएमआरसी ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया था। दरअसल जिस रूट पर भाजपा नेता मेट्रो चलवाना चाह रहे थे उस पर आबादी नहीं होने के कारण डीएमआरसी ने इसे घाटे का सौदा मान कर प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि यह विशुद्ध पेशेवर संस्थान है न कि राजनीतिक स्टंटबाजी करने वालों का गिरोह।

औद्योगिक मज़दूर कल्याण के नाम पर सात करोड़ के भवन निर्माण की तैयारी

बल्लबगढ़ (मज़दूर मोर्चा) राजनेताओं की ये खूबी रही है कि वे हर काम गरीब जनता के कल्याण हेतु करने का दावा करते हैं। चुनाव में वोट मांगते वक्त भी तमाम राजनेता गरीबों की भलाई के बड़े-बड़े वायदे करते हैं जो हमेशा खोखले साबित होते आये हैं। ऐसा ही एक दावा सेक्टर 62 में मज़दूर शेल्टर होम बनाने का किया जा रहा है। करीब एक एकड़ के भू-खंड पर सात करोड़ की लागत से दो मंजिला भवन बनाया जायेगा।

'हूडा' के अधीक्षण अभियंता संदीप दहिया के हवाले से मीडिया में आये बयान के अनुसार इस भवन निर्माण का नक्शा एवं प्रस्ताव बना कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। निर्माण स्थल परिवहनमंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिये दहिया के बयान में उन्हें भी श्रेय दिया गया है। अब क्योंकि मंत्री महोदय का नाम भी इससे जुड़ गया है तो मुख्यालय से स्वीकृति आने में देर नहीं लगेगी। बयान में कहने को तो कहा गया है कि यह भवन औद्योगिक मज़दूरों के लिये बनाया जा रहा है, साथ ही यह भी कहा गया है कि मज़दूर काम पर ले जाने वालों का खुले में, सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए इंतजार करते रहते हैं। विदित है कि इस तरह से काम का इंतजार करने वाले दिहाड़ीदार मज़दूर शहर के अनेक ठिकानों पर एकत्रित होते रहते हैं। यदि सरकार को वास्तव में ही ऐसे दिहाड़ीदार मज़दूरों की कोई चिंता है तो उसे ऐसे उन तमाम स्थानों पर शेल्टर बनाने चाहिये, जहां ये काम पर ले जाने वाले का इंतजार करते हैं। इन्हें किसी भी तरह से औद्योगिक मज़दूर नहीं कहा जा सकता। बयान में बताया गया है कि बनने वाले भवन में डिस्पेंसरी, यूनियन ऑफ़िस, दो शौचालय, एक रसोई घर आदि-आदि बनाये जायेंगे। इसमें एक सेवादार भी तैनात किया जायेगा ताकि मज़दूरों को विश्राम करने में कोई असुविधा न हो। बयान में यह नहीं बताया गया कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ़ की भर्ती करके उसे चलाने का काम खुद 'हूडा' करेगा अथवा ज़िला स्वास्थ्य विभाग से करवायेगा? सर्वविदित है कि ज़िला स्वास्थ विभाग में, पहले से ही बने अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ़ की तैनाती नगण्य है।

संदर्भवश सेक्टर 55 में दो एकड़ के भूखंड पर बने तीन मंजिला अस्पताल में स्टाफ़ के अभाव में कौवे बोल रहे हैं। लगभग यही स्थिति सेक्टर तीन तथा सेक्टर 30 के एफआरयू अस्पतालों की भी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने तथा अपनी जेबों में कमीशन भरने के लिये ऐसे भवनों का निर्माण करना जरूरी होता है।

Paytm
MM
Majdoor Morcha
UPI ID: 8851091460@paytm
8851091460
Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112 Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

योगी सरकार द्वारा रामनवमी में सभी जिलों को एक लाख रुपये दिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

इलाहाबाद (मज़दूर मोर्चा) उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च को समस्त जिलाधिकारी व मण्डलायुक्तों को रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की जारी अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दाखिल याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई करेंगे। समाजसेवी राजीव यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार के इस कृत्य से संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना होती है। याचिका में कहा गया है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है जिसमें सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता है जबकि प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में साफ तौर पर जनता के पैसे का उपयोग धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का गैर-धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाता है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में जिलाधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। प्रति जनपद में रामनवमी के दिन प्रस्तुति करने वाले कलाकारों को संस्कृति विभाग द्वारा एक लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

उपरोक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम की ओर से जारी किया गया है। उनके प्रति याचिका में यह कहा गया है कि अपने राजनीतिक प्रभुओं को खुश करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण पोस्टिंग को बचाये रखने की गरज से एक लोक सेवक के रूप में लिए गए शपथ का उल्लंघन किया गया है। जो कि संविधान के प्रति एक अपराध है और जानबूझकर किये गए इस अपराध के लिए उन्हें दंडित करने की भी मांग की गई है।

याचिका में आगे कहा गया है कि किसी भी सरकार के द्वारा किये जाने वाले इस तरह के कार्य आधुनिक भारत के निर्माताओं के संघर्षों, स्वप्नों और भारत निर्माण के उनके मॉडल के ऊपर सीधा प्रहार है जो कि भारतीय राष्ट्र के ऊपर एक हमला है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421